



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2014/ज्येष्ठ 19, 1936

No. 146]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2014/JYAISTHA 19, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2014

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, चीन जन गण और ताइवान (चीनी ताइपेई) से पोटैसियम कार्बोनेट के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 15/12/2014—डीजीएडी.—यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है), ने दिनांक 16 जनवरी, 2004 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/42/2002—डीजीएडी द्वारा चीन जन गण, कोरिया, यूरोपीय संघ और ताइवान (चीनी ताइपेई) (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटैसियम कार्बोनेट (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। उक्त जांच परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 37/2004—डीजीएडी के द्वारा उपर्युक्त देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था। तत्पश्चात् प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच की थी और दिनांक 20 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/04/2008—डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस शुल्क को दिनांक 10 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 61/2009—सीमा शुल्क द्वारा बढ़ाया गया।

समीक्षा हेतु अनुरोध

2. यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के अनुसार यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को पहले नहीं हटाया जाएगा तो उसे लागू करने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर वह निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी को इस उपाय की समयावधि समाप्त होने की तारीख से तर्कसंगत अवधि की भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. और यतः उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार गुजरात अलकलिस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ने एक विधिवत रूप से एक साक्ष्यांकित आवेदन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 10 जून, 2009 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 61/2009 द्वारा उपर्युक्त देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की गई है।

4. प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना की जांच की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को देखा है कि कोरिया गणराज्य, चीन जन गण और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है इसके अलावा प्राधिकारी ने देखा है कि घरेलू उद्योग में यूरोपीय संघ के मामले में स्वयं स्वीकार किया है कि पाटन मार्जिन नकारात्मक है और यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने को साबित नहीं किया है। अतः प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर यह मानते हैं कि यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, चीन जन गण और ताइवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से पाटन की भरपाई के लिए ऐसे शुल्कों को जारी रखने की जरूरत की जांच करने के लिए लागू पाटन रोधी शुल्क को बनाए रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की कार्यवाही करना उचित होगा और इस बात की जांच करना कि क्या यदि शुल्कों को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता

5. यह याचिका गुजरात अलकलिस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे घरेलू उद्योग या याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई है, जो संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि न तो उन्होंने संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह भारत में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित है। याचिकाकर्ता के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य ज्ञात उत्पादक हैं अर्थात् आंध्रा शुगर्स लिमिटेड और श्री रायलसीमा अलकलिस एण्ड एल्याड केमिकल्स लिमिटेड। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः याचिकाकर्ता पाटन रोधी नियमावली के अर्थ के भीतर वर्तमान याचिका दायर करने की योग्यता को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं

6. विचाराधीन उत्पाद "पोटेसियम कार्बोनेट" है। पोटेसियम कार्बोनेट एक सफेद द्रव अकार्बनिक योगिक है जो पाउडर और दानेदार रूप में होता है। यह जल में घुलनशील और अल्कोहल में अघुलनशील होता है। इसका रसायनिक सूत्र K_2CO_3 है और (एचएस) कोड 2836 40 00 है।

7. वर्तमान याचिका पहले लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए है। पूर्ववर्ती जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई समस्या नहीं है। किसी भी मामले में प्रस्तावित जांच मौजूदा पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा होने की वजह से प्रस्तावित जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पहले समाप्त निर्णायक समीक्षा जांच के उत्पाद के दायरे के समान है।

8. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु इन मापदंडों के अनुसार आयातित उत्पाद के समान वस्तु है जैसे भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जांच के बाद प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

संबद्ध देश

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, चीन जन गण और ताइवान (चीनी ताइपेई) हैं।

सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के साक्ष्य लेने के प्रयास किए गए थे। प्रकाशित स्रोतों से कीमत प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए थे परंतु संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पादन की कीमतें उपलब्ध कराने वाला कोई प्रकाशन नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह दावा भी किया है कि उत्पाद की कीमतें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कीमत का सौदा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होता है और इसलिए ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता ने आयातित कच्ची सामग्री की लागत और तर्कसंगत लाभ के साथ घरेलू परिवर्तन लागत के आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है।

निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु चीन जन गण हेतु चीन सीमा शुल्क के आंकड़ों और कोरिया तथा ताइवान के लिए डीजीसीआईएस के प्रकाशित आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, बैंक प्रभार, वेट समायोजन (चीन जन गण के लिए) निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर पाटन किया जा रहा है जिससे समीक्षा जांच की शुरुआत सही साबित होती है।

पाटन और क्षति का जारी रहना या उनकी पुनरावृत्ति

13. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल मात्रात्मक और कीमत प्रभावों के रूप में वास्तविक क्षति होना जारी है जो कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री से स्पष्ट है। यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में कुछ मानदण्डों में सुधार हुआ है तथापि यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटन रोधी शुल्क हटाया जाता है तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की क्षमताएं भारत में मांग की तुलना में काफी अधिक हैं और तदनुसार यदि प्राधिकारी द्वारा लगाया गया पाटन रोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन के पुनरावृत्ति होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं जो समीक्षा जांच की शुरुआत को न्यायसंगत ठहराते हैं।

जांच की शुरुआत

14. समीक्षा की आवश्यकता को साबित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और इस बात की जांच करने के लिए की क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या उसके पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए पाटन रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार एतद द्वारा निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि

15. जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014 तक की है। क्षति के रुझानों का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2010 – मार्च 2011, अप्रैल 2011 – मार्च 2012, अप्रैल 2012 – मार्च 2013 और जांच अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।

प्रक्रिया

16. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:—

- (i) इस समीक्षा में दिनांक 10 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 61/2009—सीमा शुल्क यथा संशोधित द्वारा प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।
- (ii) नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
कमरा सं. 132, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों का उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना होगा।

समय-सीमा

19. घरेलू उद्योग से सूचना की प्राप्ति पर सभी हितबद्ध पक्षकार, जिनके पते उपलब्ध हैं, को एक पत्र द्वारा कहा जाएगा कि वे अपनी टिप्पणियां इस पत्र को जारी करने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजें। कोई हितबद्ध पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध करने वाले पक्षकार को यदि उसके किसी भाग पर

गोपनीयता का दावा किया गया है तो उसके दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करने होंगे:

- (क) गोपनीय रूप में अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि), और
- (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)

21. “गोपनीय” या “अगोपनीय” अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों अंशों की साफ्ट कापियां और हार्ड कापियां प्रत्येक की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22. गोपनीय अंश में वह सभी सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय और/या अन्य सूचना है जिसे ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति गोपनीय होने का दावा करता है। गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु या अन्य कारण की वजह से दावा की गई गोपनीयता संबंधी सूचना के लिए सूचना प्रदान करने वाले को प्रस्तुत सूचना के साथ वह कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है (यदि सूचीबद्ध करना संभव न हो)। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. प्राधिकारी संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विषिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2014

(SUNSET REVIEW)

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty imposed on Import of Potassium Carbonate originating in or exported from EU, Korea RP, China PR and Taiwan (Chinese Taipei).

No. 15/12/2014-DGAD:—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-dumping Duty on imports of Potassium Carbonate (herein after referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, Korea, European Union and Taiwan (Chinese Taipei)

(herein after referred to as the subject countries), vide Final Findings Notification No 14/42/2002-DGAD dated 16th January, 2004. On the basis of the said findings, the Central Government imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries vide Notification No 37/2004 dated 20th February, 2004. Subsequently, the Authority conducted a sunset review investigation and recommended extension of anti-dumping duty vide Notification 15/4/2008-DGAD dated 20th May, 2009. The duty was extended vide Notification No. 61/2009-Customs dated 10th June, 2009.

Request for Review

2. Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And, whereas, in terms of the above provision, Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd has approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Ministry of Finance Notification No 61/2009-Customs dated 10th June, 2009 and sought the continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

4. The Authority has examined the data/information submitted by the domestic industry in this regard. The Authority has observed the submission of domestic industry that the dumping of the subject goods originating in or exported from subject countries has continued and is causing injury to the domestic industry. The Authority, therefore, on the basis of prime facie evidence given by the applicant considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were allowed to cease.

Domestic Industry and Standing

5. The application has been filed by Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. (hereinafter referred to as the domestic industry or the petitioner), a major producer of the subject goods. The petitioner has claimed that it has not imported the subject goods nor is related to exporters from the subject countries or importers in India. There are two other known producers of the subject goods in India, apart from the petitioner, viz., Andhra Sugars Limited and Sree Rayalaseema Alkalies & Allied Chemicals Ltd. It is noted from the data furnished by the petitioner that the production of petitioner constitutes a major proportion of total domestic production of subject goods in India. The petitioner therefore satisfies the requirement of standing to file the present petition and constitutes 'Domestic Industry' within the meaning of the AD Rules.

Product under Consideration and Like articles

6. The product under consideration is "Potassium Carbonate". Potassium Carbonate is a white, deliquescent inorganic compound, available in powder and granules form, soluble in water and insoluble in alcohol, having chemical formula K_2CO_3 and having an ITC (HS) code 2836 40 00.

7. The present petition is for sunset review of the anti dumping duty earlier imposed. The previous findings do not show any issue with regard to product under consideration. In any case, proposed investigation being review of existing anti dumping duty, the scope of the product under consideration in the proposed investigation remains the same as the scope of the product in the last concluded sunset review investigation.

8. Further, the petitioner has claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. After examination, the authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject countries.

Subject Countries

9. The countries involved in the present sunset review investigations are EU, Korea RP, China PR and Taiwan (Chinese Taipei).

Normal value

10. The petitioner has claimed that efforts were made to get evidence of price of subject goods in the domestic markets of the subject countries. Efforts were also made to obtain the price from the published sources but there is no publication which provides prices of the product under consideration in subject countries. Petitioner has further claimed that the product prices are not publicly available as the prices are transacted between the producer and consumers and therefore the same are not in public domain. In view of the same, the Petitioner has constructed the normal value for the subject countries on the basis of the imported raw material cost and domestic conversion cost with a reasonable profit.

Export Price

11. Petitioner has relied upon China Customs data for China PR and published import data from DGCI&S for other subject countries for determining export price for subject countries. The export price of subject countries has been adjusted for expenses such as Ocean freight, Marine insurance, Commission, Port expenses, Inland freight expenses, Bank charges, VAT adjustment (for China PR) to arrive at the net export price. The Authority, after examination, considers that there is sufficient prima facie evidence of export price of the subject goods from the subject countries.

Dumping Margin

12. Petitioner has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries continue to be dumped prices, to justify initiation of a review investigation.

Continuation or Recurrence of Dumping and Injury.

13. The petitioners have claimed that domestic industry continues to suffer injury by way of adverse volume and price effects as evidenced by price undercutting and price underselling. Though the domestic industry's performance has improved in some parameters during the injury period, there is a likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of revocation of anti dumping duty on subject goods from subject countries. The petitioner has further claimed that capacities in subject countries for subject goods are substantially huge in comparison of the demand in India and accordingly there is likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry once the anti-dumping duties levied by the Authority are allowed to cease. The Authority considers that there is sufficient prima facie evidence of recurrence of dumping and injury caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries to justify initiation of a review investigation.

Initiation

14. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

15. The period of investigation (POI) is from April 2013 – March, 2014. For the purpose of analyzing trends of injury, the data of previous three years, i.e., Apr'10-Mar'11, Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13 and the period of investigation will be considered.

Procedure

16. The following procedure will be followed.

- i. The review will cover all aspects of the final findings of the original investigations published vide Notification No 61/2009-Customs dated 10th June, 2009 as amended.
- ii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information:

17. The exporters in subject countries, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce,
Room No.132, Udyog Bhawan
New Delhi -110011

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit:

19. On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification.

Submission of information on confidential basis

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

22. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File:

27. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority